पहल के परिणाम

किसी नीति या योजना की समीक्षा के लिए सौ दिन की अवधि पर्याप्त नहीं होती है. लेकिन, अगर प्रारंभ में ही उत्साहजनक परिणाम आने लगें और उससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलने लगे, तो ऐसी पहल का उल्लेख आवश्यक हो जाता है. आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सौ दिनों में 6.85 लाख लाभुकों ने निःशुल्क उपचार कराया है और पांच लाख से अधिक लोगों के उपचार के दावे का निपटारा करते हुए उसके लिए धन भी मुहैया करा दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत कार्यरत प्रणाली की कार्यक्षमता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि हर दिन पांच हजार दावों का निपटारा हुआ है. चालू वित्त वर्ष के अंत तक 25 लाख लोगों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. इस महत्वाकांक्षी योजना में 10 करोड़ से अधिक परिवारों यानी देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या को अस्पतालों में भर्ती होकर उपचार कराने का अवसर मिला है. वंचित परिवार 16 हजार अस्पतालों में हर साल पांच लाख रुपये तक का उपचार करा सकते हैं. इस योजना में व्यय का 60 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार को वहन करना है तथा शेष योगदान राज्यों का है. इस पहल को टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य-संबंधी योजनाओं के साथ भी जोड़कर देखा जाना चाहिए. टीकाकरण अभियान के तीव्र विस्तार ने भविष्य के लिए स्वस्थ पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त किया है. इससे आनेवाले समय में आयुष्मान योजना और स्वास्थ्य सेवा पर दबाव कम होने की आशा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की है कि 2025 तक स्वास्थ्य के मद में सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा. अभी यह एक प्रतिशत से कुछ ही अधिक है. सरकार ने 2022 तक डेढ़ लाख स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में बताया था कि हमारे देश में लोगों को उपचार के व्यय का लगभग 68 प्रतिशत भाग स्वयं वहन करना पड़ता है. इस मामले में वैश्विक औसत मात्र 18 प्रतिशत के आसपास है. निर्धनता और उपचार के भारी व्यय के कारण हर साल 4.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं. अक्सर लोग महंगे उपचार के कारण समय पर अस्पताल नहीं जाते और बाद में सामान्य बीमारी भी गंभीर रूप धारण कर लेती है. ऐसे में आयुष्मान भारत के दायरे को तेजी से विस्तार देने की आवश्यकता है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र को सहभागिता के साथ निवेश बढ़ाने और दावों के निपटारे की समुचित व्यवस्था बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है. इस योजना के बारे में जागरूकता, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, बढ़ाने में सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मीडिया की भी बड़ी भूमिका है. आयुष्मान भारत की प्रारंभिक उपलब्धियां स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने और बढ़ते रहने का हौसला देती हैं.

आयुष्मान भारत की प्रारंभिक उपलब्धियां स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने और बढ़ते रहने का हौसला देती हैं.

हिंदू होने का अर्थ!

तरुण विजय
वरिष्ठ नेता, भाजपा
tarunvijay55555@gmail.com

जब-जब हिंदुओं को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा का अवसर मिला, तब-तब विदेशी विधर्मियों से बढ़कर स्वदेशी स्वधर्मियों ने ही अपने अहंकार और भीतरी विरोधियों से शत्रुता को प्रमुखता देते हुए मार्ग में बाधाएं डालीं और एक तरह से मिलती-मिलती विजय पानीपत की पराजय में बदलती चली गयी. दुर्भाग्य से इतिहास भी तो पराजय का ही पढ़ाया जाता है, पर पानीपत कितनों को याद होगा? यह सवाल जरा स्वयं से पूछिए. जो समाज अपनी जय और पराजय की स्मृति नहीं रखता, उसका क्या भविष्य होगा? भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बारे में अदालत ने जो फैसला दिया है, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में जो लोग हिंदू संस्कृति या हिंदू हित की बात राजनीति में करने के लिए उतरते हैं, उन्हें बाहर और भीतर से कितने आघात एवं झूठे और बेबुनियाद आरोप सहन करने पड़ते हैं. लेकिन, यह भी सच है कि कई बार लम्हों की खता सदियों तक झेलनी पड़ती है.

हिंदू भूल गये कि अगर स्वामी दयानंद ने पाखंड खंडिनी पताका उठाकर हिंदुओं के आलस्य और रूढ़िवादिता के साथ पारस्परिक शत्रुता और कर्मकांड में डूबे रहने पर करारे प्रहार नहीं किये होते तथा परंपरागत हिंदुओं की अहमन्यता को वेद शक्ति के प्रहार से चूर-चूर नहीं किया होता, तो उत्तर भारत ईसाई बन गया होता. स्वामी दयानंद ने जातिप्रथा के आधार पर भेदभाव को हमारे घरों से दूर किया और अहंकारी ब्राह्मणों के कर्मकांड को चुनौती देते हुए शुद्धि आंदोलन चलाया तथा धर्मांतरित होकर ईसाई तथा मुसलमान बन चुके हिंदुओं को वापस लौटा लाये.

स्वामी श्रद्धानंद शुद्धि आंदोलन के महापुरुष थे और उनका कार्य इतना प्रखर तथा सफल था कि कट्टर मुसलमान भी उनका सम्मान करते थे और वे इतिहास के अकेले हिंदू संन्यासी हुए, जिन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद में मुसलमानों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया. लेकिन राजनीति और धनी एवं उच्च जाति के अहंकारी हिंदुओं के कारण समाज में आज भी जाति भेद प्रबल है. अनुसूचित जाति के नौजवान शादी में घोड़े पर चढ़कर बारात ले जाते हैं, तो उन्हें उतार दिया जाता है, अपमानित किया जाता है. विद्यालयों में उनके बच्चों को अक्सर ताने सुनने पड़ते हैं.

पिछले महीने मैं मेरठ में वाल्मीकि समाज के प्रभावशाली बच्चों के एक सम्मान समारोह में गया था. वाल्मीकि बच्चे प्रतिभा और कुशलता में किसी से कम नहीं हैं. लेकिन, उन्हें समाज में जो भेदभाव सहना पड़ता है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते. मुझे एक प्रोफेसर मिले, आप उनके अनुभव सुनेंगे, तो आंखों में आंसू और हृदय में गुस्सा उबलने लगेगा. सब कुछ सही होते हुए भी जब कॉलेज के प्रबंधकों को पता चलता है कि वे अनुसूचित जाति से हैं, तो या तो उन्हें नौकरी नहीं देते या स्तर से कम पर देते हैं.

> एक जाति सदियों से इस देश में सफाई कर्मचारी बनी हुई है. यह किस आंबेडकर का सम्मान है और हिंदू समाज की कौन सी धार्मिक महानता है?

कौन स्वाभिमानी समाज या व्यक्ति होगा, जो जाति के आधार पर या किसी भी कारण से इस तरह के तिरस्कार को सहन करेगा? एक बार मैंने स्वयं एक हवाई अड्डे पर देखा कि एक सांसद अपने बगल के यात्री से सिर्फ इसलिए भिड़ गये, बल्कि उसे झापड़ मार दिया, क्योंकि वह यात्री लाइन में सांसद जी से आगे आ गया था.

एक जाति सदियों से इस देश में सफाई कर्मचारी बनी हुई है. यह किस आंबेडकर का सम्मान है और हिंदू समाज की कौन सी धार्मिक महानता है? मूर्तियां, मंदिर, आश्रम और करोड़ों रुपये लगाकर होनेवाले भगवद् भजन-कीर्तन के कार्यक्रम लगातार बढ़ रहे हैं. हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर और शनिवार को शनि देवता के नये-नये मंदिरों के सामने भीड़ बढ़ रही है. लेकिन, जिस समाज के हृदय में राम, अधरों पर राम, नाम में राम (अधिकतर अनुसूचित जातियों के), हिंदू जगजीवन राम से लेकर अर्जुन राम तक सब कुछ सहन करते हुए भी राम का साथ नहीं छोड़ते, ऐसे सच्चे और शौर्यवान रामभक्तों के साथ हम लोग क्या व्यवहार करते हैं?

राजनीति में अनुसूचित जाति के लोग किसी भी दल में आगे नहीं बढ़ाये जाते. उनका अगला टिकट मिलना या ना मिलना उन लोगों के हाथ में रहता है, जो चुनाव क्षेत्र में छोटी जाति, बड़ी जाति का आंकड़ा देखकर टिकट का आवंटन करते हैं. अनुसूचित जाति के बच्चे-बच्चियों पर जब हमला होता है, या उनका अपमान होता है, तो क्या आपने कभी देखा कि संसार त्यागकर समस्त प्राणियों को एक समान माननेवाले संत-महात्मा या हिंदू सांसद-विधायक लोग अनुसूचित जाति के घर-परिवारों में जाकर उनके साथ खड़े होते हों और जाति भेद के आधार पर उनसे अन्याय करनेवाले हिंदुओं को समझाकर सामाजिक समता स्थापित करते हों? अगर कहीं ऐसा कोई वातावरण बनते दिखता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साधारण अनाम, अजान कार्यकर्ता चुपचाप ही सामाजिक समरसता के लिए अनुसूचित जाति बस्तियों और वाल्मीकि मंदिरों में काम करते दिखते हैं. पर हालात बहुत कठिन तथा जटिल हैं.

समता की बात करनेवालों को 14 अक्तूबर, 1956, नागपुर की दीक्षा भूमि का दृश्य कभी भी भूलना नहीं चाहिए. उस दिन डॉ आंबेडकर लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध हो गये थे. अगले दिन 15 अक्तूबर, 1956 को दिया गया आंबेडकर का भाषण हर हिंदू को पढ़ना चाहिए और स्वयं से पूछना चाहिए कि आप अपने ही हिंदू भाई-बहनों के साथ केवल तब तक ही तो भेदभाव कर सकते हो, जब तक वे स्वयं को हिंदू कहते हैं?

हिंदू समाज एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है. उत्तराखंड से अरुणाचल प्रदेश तक बड़ी संख्या में हिंदू विभिन्न कोणों से हम लोगों का शिकार हो रहे हैं, तथा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में उन पर हमले बढ़े हैं और संख्या का रुझान घटने की तरफ चल पड़ा है. सड़कें, पानी, बिजली, राजनीति करते रहिए, लेकिन अगर सदियों से केवल हिंदू होने के कारण जो विभिन्न दिशाओं से हमले झेल रहे हैं, वही आज भी स्वयं को अपनी विरासत, परंपरा तथा धार्मिकता पर चोट होते देखने पर विवश होंगे, तो हे परम पराक्रमी विभिन्न दलों के नेताओं, भारत अपने ही समाज के साथ पुनः अन्याय होते देख सुखी नहीं हो सकता. पद, पैसा और प्रभाव तो काबुल, रावलपिंडी, लाहौर और कराची के हिंदुओं के पास भी कम नहीं था. यह बात भी क्या याद दिलानी पड़ेगी?

पड़ोस में भू-राजनीतिक समीकरण

आलोक कु. गुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर,
दक्षिण बिहार केंद्रीय विवि
akgalok@gmail.com

> संवैधानिक संकट को संभालने के बहाने भारत का पड़ोस में हस्तक्षेप वहां की जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को समझ में आता है. अतः भारत के 'पड़ोस पहले' की विदेश नीति का मतलब 'पड़ोस में हस्तक्षेप' नहीं, बल्कि 'पड़ोस में निवेश' होना चाहिए.

बांग्लादेश में बीते 30 दिसंबर को हुए 11वें संसदीय चुनाव में शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग की अप्रत्याशित जीत हुई. उन्हें वहां की 300 सदस्यीय संसद में 288 सीटों पर जीत मिली. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसमें विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का सफाया हो गया. आरोप-प्रत्यारोप के मध्य विपक्ष ने परिणाम को खारिज करते हुए चुनाव प्रक्रिया को नकार दिया है. यह एक संसदीय लोकतंत्र की प्रथा रही है. इस बार विपक्ष एक गठबंधन 'नेशनल यूनिटी फ्रंट' (जातीय ओकिया फ्रंट) बनाकर आवामी लीग को चुनौती दे रहा था, जिसका नेतृत्व बीएनपी कर रही थी और गोनो फोरम, जेएसडी, नागरिक फ्रंट और कृषक श्रमिक जनता लीग जैसे अन्य दल शामिल थे.

गौरतलब हो कि बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं. चुनाव के दौरान हिंसा और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चला, जिसमें लगभग 17 लोगों की जान भी गयी. सत्ताधारी दल और नेताओं पर मानवाधिकार हनन के आरोप भी लगाये गये.

लगभग 16 करोड़ जनसंख्या वाले बांग्लादेश की जातीय संसद (पार्लियामेंट) 350 सदस्यों वाली है, जिसमें 300 सीटों के लिए प्रत्यक्ष आम चुनाव होते हैं और 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. प्रत्यक्ष चुनाव 'जो पहला सो मीर' की तर्ज पर होता है. पचास सीटों का वितरण चुनाव में भाग लेनेवाले दलों को जितने प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं, उसके अनुपात में किया जाता है. परंतु सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 151 सांसदों की जरूरत होती है. करीब 71 वर्षीय शेख हसीना, जो आवामी लीग का 1981 से नेतृत्व कर रही हैं, चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी. इस चुनाव में पहली बार लगभग छह संसदीय क्षेत्रों में इवीएम का इस्तेमाल भी किया गया.

चुनाव में शेख हसीना का मुख्य मुद्दा था बांग्लादेश की पिछले दशक में आर्थिक उन्नति और सराहनीय जीडीपी ग्रोथ. उनके कार्यकाल में कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और वर्तमान में चीन के बाद बांग्लादेश इस क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है. शेख हसीना ने म्यांमार से आनेवाले लगभग 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या को भी प्रभावी ढंग से संभाला था. भारत के साथ अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को कायम रखते हुए चीन के साथ भी सामंजस्य बनाये रखा. उनकी विदेश नीति भी प्रभावी एवं सशक्त रही. उनकी जीत केवल शानदार ही नहीं, बल्कि सत्ता-विरोधी लहर की चुनौती झेल रही हसीना को उनके द्वारा किये गये कार्य और विकास पर आम-जनता की स्वीकृति की इबारत भी है. ऐसा तब संभव हो सका, जब उन पर मीडिया और विपक्ष के लोगों पर कड़े दंडात्मक करवाई के लिए मानवाधिकार हनन के गहन आरोप लगाये जाते रहे. पिछले दस वर्षों के बाद इस चुनाव में लगभग सभी दलों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार भी किये. इस चुनाव में लगभग 39 राजनीतिक दलों ने अपने भाग्य आजमाये.

बांग्लादेश चुनाव परिणाम भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी अच्छी खबर है. गौरतलब है कि 2014 के विवादास्पद संसदीय चुनाव में जब विश्व के ज्यादातर राष्ट्र विरोध जता रहे थे, तब भारत ही बांग्लादेश के पक्ष में खड़ा था. परंतु इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला. यह परिणाम दक्षिण-एशिया के बदलते भू-राजनितिक समीकरण का द्योतक है. मालदीव में सोलिह की जीत के साथ पड़ोस से भारत के लिए अच्छी खबर आने लगी है. पिछले वर्ष ही नेपाल में वाम गठबंधन की जीत हुई, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि ऐसा चीन के हस्तक्षेप के कारण ही संभव हो पाया था. श्रीलंका में भी लगभग दो महीने तक राजनीतिक उथल-पुथल रही और ऐसा लगने लगा था कि एक बार फिर से महिंदा राजपक्षे की सरकार सत्ता पर काबिज हो जायेगी, जिसका चीन के साथ प्रगाढ़ संबंध है. ऐसा होता तो श्रीलंका पर फिर से भारत की पकड़ ढीली पड़ जाती. एक लंबे राजनीतिक संकट के बाद पूर्व सरकार वापस सत्ता पर कायम हो गयी. भूटान के साथ भारत का संबंध एक स्वर्णिम युग के दौर से गुजर रहा है. पिछले वर्ष जुलाई में भूटान के राजा और फिर दिसंबर में प्रधानमंत्री शेरिंग का भारत दौरा हुआ, जिसके मार्फत संबंधों में साझा-सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने के प्रयास हुए. साथ ही विकास के अन्य कार्यक्रम पर भी वार्ता हुई. पाकिस्तान में भी इमरान खान की सरकार के आने के बाद से भारत के साथ वार्ता प्रारंभ करने की ललक दिख रही है. कुल मिलाकर भारतीय पड़ोस की भू-राजनीति भारत के पक्ष में दिख रही है, जिसके प्रति भारत को सक्रीय रहकर अपने हित में बनाये रखने की आवश्यकता है.

बीएनपी का गठबंधन के तहत चुनाव में हिस्सा लेना बांग्लादेश में लोकतंत्र के परिपक्व होने की ओर इंगित करता है. संवैधानिक संकट को संभालने के बहाने भारत का पड़ोस में हस्तक्षेप वहां की जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को समझ में आता है. अतः भारत के 'पड़ोस पहले' की विदेश नीति का मतलब 'पड़ोस में हस्तक्षेप' नहीं, बल्कि 'पड़ोस में निवेश' होना चाहिए. भारत अगर पड़ोस में विपक्षी दलों के लिए मुद्दा बनता है, तो यह भारत के लिए शुभ नहीं है. भारत को मालदीव और बांग्लादेश में हुए भू-राजनीतिक लाभ को संभालने और इस अनुभव को राजनय में शामिल करना भी जरूरी है.

आपके पत्र

नैतिकता की शिक्षा जरूरी

शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार आया है, परंतु आज भी नैतिक शिक्षा का घोर अभाव है. युवा मेहनत कर सफलता पा लेते हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही अपने पद का दुरुपयोग करते हैं. समाज में लड़कियों और महिलाओं के प्रति गलत नजर रखते हैं. दहेज के विरुद्ध लंबी सलाह देने वाले पढे-लिखे लोग भी अपनी बारी आने पर दहेज के रूप में एक मोटी रकम की मांग कर देते हैं. समाज में वृद्धा आश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है और पढ़े-लिखे और समृद्ध लोग अपने माता-पिता को इसमें जाने को मजबूर कर देते हैं. यह मुख्य रूप से नैतिक शिक्षा में पतन के कारण ही है. यदि बच्चों को शुरू से ही नैतिकता की शिक्षा दी जाये, तो आने वाले दिनों में बड़े होकर वे एक बेहतर कल का निर्माण करेंगे. सरकार को तो अपने स्कूली पाठ्यक्रम में इसे जरूर ही शामिल कर लेना चाहिए.

सरोज कुमार महतो, गिरिडीह

निश्चित अवधि में पूरी हो सजा

बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए कानून में कठोर सजा के प्रावधान किये गये हैं. साथ ही बच्चों की अश्लील फिल्मों और सामग्री की उपलब्धता पर भी कठोरता से अंकुश लगाने की पहल हुई है. केंद्र सरकार ने बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा कानून में व्यापक संशोधन करने और बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान करने का निश्चय किया है. लेकिन, सवाल यह है कि क्या कानून में संशोधन करके ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा करना ही पर्याप्त है? दिसंबर 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद सजा को अत्यधिक कठोर बनाया गया, लेकिन अभी तक बलात्कारी और हत्या के दोषियों के खिलाफ मौत की सजा पर अमल नहीं हो सका है. बलात्कार के आरोपी को सजा देने की समूची कानून व्यवस्था एक निश्चित अवधि में पूरा करने के प्रावधान की आवश्यकता है. निश्चित अवधि के अभाव में कठोर सजा का प्रावधान भी बेमानी लगता है.

अभिजीत मेहरा, गोड्डा

नये साल में पीएम का इंटरव्यू

देश में राम मंदिर की तेज होती हवा और तमाम प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को साफ कर दिया कि राम मंदिर बनाने के लिए सरकार का अध्यादेश लाने का कोई इरादा नहीं है. इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होनी जरूरी है. इसके बाद सरकार अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है. मोदी के इस बयान के बाद राम मंदिर को लेकर उठने वाली चर्चा थम जानी चाहिए. साल के पहले दिन दिये अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कई विवादों पर सरकार का पक्ष स्पष्ट कर आम चुनाव से पहले विपक्ष की धारा कम करने की कोशिश की है. वे अपनी सरकार की उपलब्धियों से ज्यादा विवादित मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आये. बहरहाल मोदी के इंटरव्यू के बाद पक्ष और विपक्ष की लड़ाई शुरू हो गयी है. अब इतना तो तय है कि इन तमाम दावों और विवादों का सच जनता जानना चाहती है.

अमन सिंह, बरेली

बोधि वृक्ष

नाजुक जीवन

अगर आप अपने भीतर मौजूद, खुद से परे की प्रज्ञा, जिसे हम 'चित्त' कहते हैं, उसके लिए उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप केवल अपनी जिंदगी या अपना भाग्य ही नहीं, बल्कि आपके इर्द-गिर्द जो अरबों लोग हैं, उनकी जिंदगी और भाग्य भी तय कर सकते हैं. आप अपने इस चित्त को ईश्वरीय कृपा या कुछ और भी कह सकते हैं. क्या इंसान इन आयामों में आगे बढ़ेगा, कुछ ढूंढ़ेगा या बस पेट भरना, सोना, संतान पैदा करना और फिर एक दिन मर जाना, यही उसका लक्ष्य है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप क्या काम करते हैं या आपके पास कितना पैसा है और आप कितने अमीर हैं. आपको यह सब भूलने की कोशिश करनी है, क्योंकि मौत आपके सामने झूल रही है. ज्यादातर लोगों को यह समझ तब तक नहीं आती, जब तक कोई डॉक्टर उन्हें भयानक रोग नहीं बता देता या जब तक वे बहुत बूढ़े नहीं हो जाते या जब तक उनकी उम्र उन्हें परेशान नहीं करने लग जाती. आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं और अगले पल आपको सांस न आये तो? इसका अर्थ है आप गये. तो यह जीवन इतना नाजुक है, साथ ही यह मजबूत भी है. जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं. लेकिन इस धरती पर मेरी और आपकी तरह न जाने कितने लोग आये और यहां रहे, पर आज वे कहां हैं? सब मिट्टी बन गये. एक न एक दिन हम भी मर जायेंगे और इस धरती का हिस्सा बन जायेंगे. कल इस समय कोई और इस धरती पर चल रहा होगा. जिंदगी बहुत छोटी है. खासकर जब आप आनंद में हों, तब तो यह बहुत ज्यादा छोटी है. यह केवल उन लोगों के लिए लंबी है, जिनकी हालत दयनीय है. इंसान के पास जो विशाल संभावना है उसको देखते हुए हमें जो जिंदगी दी गयी है, वह बहुत ही छोटी है. लेकिन, उसमें भी लोग बोर हो जाते हैं और इस जीवन की सरलता को जाने बिना ही अपने आप को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के शारीरिक और मानसिक नाटक जीवन के अस्तित्व की वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं.

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

कुछ अलग

संकल्प पहले ही दिन फेल

मोहनलाल मौर्य
व्यंग्यकार
mohanlalmourya@gmail.com

मन्नालाल ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर तीन संकल्प लिये. अपने आराध्य देव को साक्षी मानकर और डायरी में लिखकर संकल्पों को पुख्ता किया. पहला संकल्प सवेरे जल्दी उठने का लिया. दूसरा, शराब नहीं पीने का और तीसरा, झूठ नहीं बोलने का. थर्टी फर्स्ट को पूरी रात पार्टी की और सवेरे नींद ने धर दबोचा. दोपहर ने नींद तोड़ संकल्प याद दिलवाया. पहला संकल्प पहले ही दिन फेल हो गया.

शाम को लंगोटिया यार धन्नालाल ने आमंत्रित किया. पार्टी-शार्टी करने के लिए- नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दी. सेम टू यू कहकर मन्नालाल ने भी शुभकामनाएं दी. अब शुभ कार्य में देरी कैसी? सो, लवली-लवली पैग बनाकर मन्नालाल को थमाते हुए धन्नालाल बोला, 'यह लो! पहला पैग नये साल के आगमन की खुशी में.'

'मैंने तो रात से पीना छोड़ दिया है.' 'अबे यार क्यों मजाक कर रहा है? मजाक छोड़ और जल्दी सी गटक जा. दूसरा पैग भी बनाना है.' 'सच में छोड़ दिया है.' 'क्यों नखरे कर रहा है यार? गिलास को तो हाथ में थाम.' 'बिल्कुल नहीं. मैंने संकल्प लिया है. संकल्प तोड़ नहीं सकता. संकल्प तोड़ दिया तो तुम्हारी भाभी नाराज हो जायेगी. मुझे घर से निकाल देगी.'

धन्नालाल मुस्कुराते हुए बोला, 'संकल्प ही तो लिया है. सात फेरे थोड़ी लिये हैं. अबे यार संकल्प लेने के लिए होता है. निभाने के लिए नहीं. ऐसा कर आज पी ले, कल से मत पीना.'

मन्नालाल दुविधा में पड़ गया. सोचने लगा पी लिया, तो संकल्प टूट जायेगा और पत्नी नाराज हो जायेगी. नहीं पिया तो मित्र नाराज हो जायेगा. मित्र की बात मान लेता हूं. आज पी लेता हूं, कल से नहीं. और एक बार में ही पूरा पैग गटक गया.

धन्नालाल बोला, 'यह हुई ना मर्दों वाली बात. यह लो दूसरा पैग दोस्ती के नाम का.' दूसरे पैग के बाद तब तक नहीं उठे, जब तक पूरी बोतल खाली नहीं हुई. मन्नालाल जब घर लौटा, तो उसके लड़खड़ाते पैर देखकर उसकी पत्नी समझ गयी. आज तो जनाब टल्ली होकर आये हैं. घर में घुसते ही क्लास लेने लगी. 'आपने तो संकल्प लिया था न, दारु नहीं पीने का?' 'हां लिया था, पर धन्नालाल माना ही नहीं. उसका मान रखने के लिए पी लिया.'

धर्मपत्नी गुस्से से लाल-पीली होती हुई बोली, 'एक तो संकल्प तोड़ दिया और ऊपर से झूठ और बोल रहे हो. आपने तो झूठ नहीं बोलने का भी संकल्प लिया था. अब उसे भी तोड़ दिया. तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. पहली बार संकल्प लिये थे, लेकिन सब तोड़ दिये. संकल्प तोड़ने से पहले जरा भी नहीं सोचा कि किसलिए ले रहा हूं और किसलिए तोड़ रहा हूं. संकल्पों को तोड़ना ही था तो लिया ही क्यों था?'

धर्मपत्नी के मुंह से सुनकर मन्नालाल मन ही मन में सोचने लगा. संकल्प नहीं लेता, तो ही अच्छा रहता. कम से कम धर्मपत्नी के ताने तो नहीं सुनता. डायरी के जिस पन्ने पर लिखकर संकल्प लिया था, उस पन्ने को फाड़कर फिर कभी संकल्प नहीं लेने का उसने अपने आप से वादा किया.

देश दुनिया से

सऊदी सहित कई अरब देशों के संपर्क में इस्राइल

इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सऊदी अरब सहित कई अरब देशों का महत्वपूर्ण घटक है इस्राइल. तसनीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने अपने ब्राजील दौरे के दौरान बीते मंगलवार को वहां स्थानीय टीवी चैनल को दिये एक साक्षात्कार में कहा कि हम सऊदी सहित कई अरब देशों के सीधे संपर्क में हैं. नेतन्याहू ने कहा कि क्षेत्र में ईरान के खिलाफ इस्राइली प्रयास इस बात का कारण बने हैं कि आज अरब जगत उनके साथ खड़ा है और तेल अवीव के साथ अरब देशों के संबंधों में काफी सुधार आया है. याद रहे कि इस्राइली शासन के अस्तित्व के आरंभ से कभी भी इस शासन के साथ सऊदी अरब के आधिकारिक संबंध नहीं थे, परंतु गुप्त रूप से इस्राइल के साथ सदैव आले सऊद के संबंध थे और सऊदी अरब ने हमेशा हर क्षेत्र में इस्राइल की नीतियों के अनुसार ही कदम उठाये हैं. इसीलिए जब ब्राजीली टीवी चैनल के पत्रकार ने भविष्य में इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ शांति वार्ता की संभावना के संबंध में प्रश्न किया, तो नेतन्याहू का कहना था कि अगर ईरान हमें तबाह करने का इरादा रखता है, तो मेरी तरफ से उससे किसी भी बातचीत से इनकार है.

World News Arabia

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है